वीकली वन लाइनर्स 6 से 12 जुलाई, 2026

PM मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से 18 बड़े नतीजे मिले, डिफेंस , एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के रिश्ते और गहरे हुए

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारत-ऑस्ट्रेलिया रिश्तों में एक बड़ी कामयाबी मिली है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीसरे सालाना समिट में 18 एग्रीमेंट और पहल सामने आईं। ये एग्रीमेंट, जिनमें डिफेंस , मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, ज़रूरी टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और कल्चरल कोऑपरेशन जैसे बड़े एरिया शामिल हैं, बताते हैं कि यह भारत-ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सबसे बड़े विस्तार में से एक है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी में नया चरण

समिट ने इस बात को फिर से कन्फर्म किया है कि मुश्किल जियोपॉलिटिकल हालात में भारत-ऑस्ट्रेलिया रिश्तों की स्ट्रेटेजिक अहमियत बढ़ रही है।

दोनों देशों ने डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन में सहयोग की ज़रूरत पर सहमति जताई, साथ ही एक फ्री, ओपन, इनक्लूसिव और रूल-बेस्ड इंडो-पैसिफिक रीजन के कॉमन विज़न के लिए कमिटमेंट को दोहराया।

ये 18 नतीजे रीजनल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए ज़रूरी मामलों में सहयोग करने के लंबे समय के इरादे को दिखाते हैं।

प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान हुए नतीजों की सूची

1. रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा (JDDSC)
2. समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप (MSCR)
3. ऊर्जा सुरक्षा पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त घोषणा
4. भारत-ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को फाइनलाइज़ करना
5. साइबर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया-भारत साझेदारी (PACTS)
6. भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और ऑस्ट्रेलिया के MBC के बीच समझौता ज्ञापन
7. डिफेंस कॉलेज में भारतीय मिलिट्री ऑफिसर (2028-29)
8. खनन और एमईटीएस उत्कृष्टता केंद्र पर समझौता ज्ञापन
9. फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी ब्रांच बेंगलुरु में
10. NCVET और ASQA के बीच समझौते पर सहमति
11. तीन भारतीय कलाकृतियों का जीर्णोद्धार
12. रूफटॉप ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत
13. ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसीआईटीआई) साझेदारी पर समझौता ज्ञापन
14. जियोसाइंस ऑस्ट्रेलिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन
15. पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस समझौता
16. CSIR और मेलबर्न विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन
17. एसआरएफटीआई कोलकाता और ग्रिफिथ फिल्म स्कूल के बीच समझौता ज्ञापन
18. गुरुग्राम में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कैंपस

इन पहलों का महत्व

तीसरे इंडिया-ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट के नतीजे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के कॉन्सेप्ट से कहीं आगे हैं।

इन समझौतों का मतलब है ज़रूरी सेक्टर्स में बेहतर सहयोग, जिनमें शामिल हैं,

- रक्षा और हिंद-प्रशांत सुरक्षा
- नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करें
- असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पहल
- खनिज मंत्रालय सहयोग
- शिक्षा और कौशल विकास सहयोग
- अनुसंधान
- सांस्कृतिक विरासत संरक्षण

इन एक्टिविटीज़ का मकसद भारत के स्ट्रेटेजिक रिश्तों को मज़बूत करना और इस इलाके में स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और सस्टेनेबल ग्रोथ पक्का करना है।

नए EPF विड्रॉल नियम 2026: 3-दिन में क्लेम सेटलमेंट, 25% बैलेंस नियम, ऑनलाइन प्रोसेस और EPFO के नए बदलाव

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) ने अपने नए EPFO 3.0 डिजिटल इनिशिएटिव के तहत बड़े सुधार किए हैं, और प्रोविडेंट फंड (PF) विड्रॉल को तेज़, आसान और डिजिटल बना दिया है। ये EPF विड्रॉल रूल्स 2026 कुछ बदलाव लाएंगे। o ज़रूरी बदलावों में 3-दिन में क्लेम सेटलमेंट, ₹5 लाख की ज़्यादा ऑटो-प्रोसेसिंग लिमिट, आसान विड्रॉल कैटेगरी और 25% मिनिमम बैलेंस रखने का नियम शामिल हैं । नए EPF विड्रॉल रूल्स 2026 के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह सब यहाँ है।

नए EPF विड्रॉल नियम 2026 क्या हैं?

EPFO ने पैसे निकालने के प्रोसेस को आसान बना दिया है, कई पैसे निकालने की कैटेगरी को आसान स्ट्रक्चर से बदल दिया है और डिजिटल सर्विस को बढ़ाया है।

इस नए फ्रेमवर्क का मकसद पार्शियल विड्रॉल को आसान बनाना है, साथ ही यह पक्का करना है कि कर्मचारी रिटायरमेंट या फाइनल सेटलमेंट तक अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स का कुछ हिस्सा अपने पास रखें।

ईपीएफ निकासी नियम 2026 की मुख्य बातें

3 दिन में ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट

आधार-लिंक्ड और वेरिफाइड KYC वाले एलिजिबल ऑनलाइन PF एडवांस क्लेम अब सिर्फ़ तीन वर्किंग डेज़ में प्रोसेस हो जाएंगे, और इससे पहले का प्रोसेसिंग टाइम, जो लगभग 7 से 20 दिन का होता था, काफ़ी कम हो जाएगा।

अनिवार्य 25% शेष राशि प्रतिधारण

नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को नौकरी में रहते हुए अपने कुल EPF बैलेंस का कम से कम 25% अपने पास रखना होगा।

Test Prime By Adda247

ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION

Test. Analyze. Improve. Repeat.

Don't just prepare. Perform.

Test Prime – built only for mock tests.

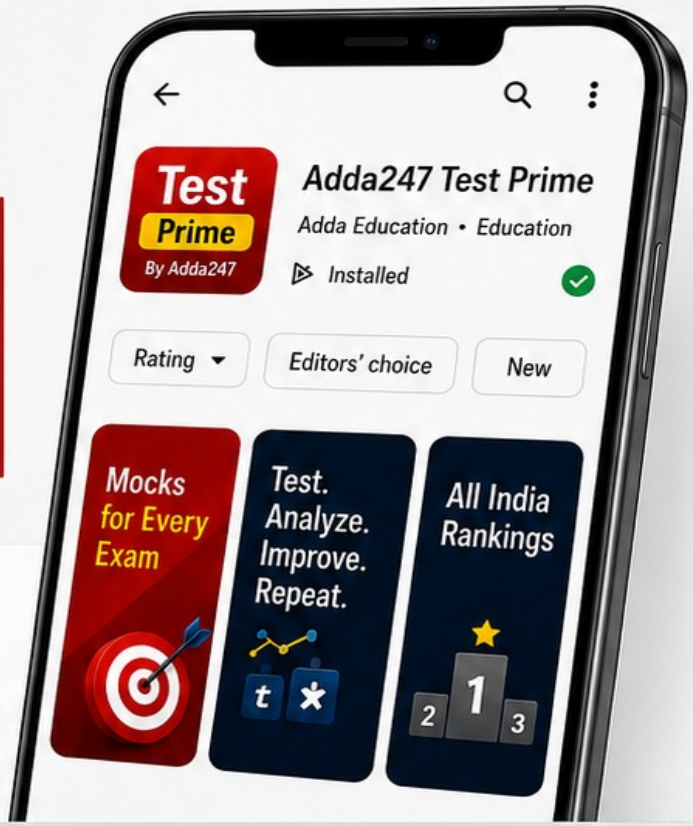

1,50,000+ Mock Tests

25,000+ Previous Year Papers

800+ Exam Covered

500% Refund on Selection

5 lakh+ Free Quizzes

Daily Free PDFs

Top Alerts Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- Multilingual
- Detailed Solution
- Strong and Weak Areas
- All India Rankings

- Safe & Reliable
- Trusted by Lakhs of Aspirants
- Your Success, Our Mission

DOWNLOAD TEST PRIME

Your Success Partner!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

12 महीने की वर्दी सेवा की आवश्यकता

पहले, अलग-अलग विड्रॉल के लिए लगभग 3 से 7 साल की सर्विस ज़रूरी होती थी; अब ज़्यादातर पार्शियल विड्रॉल बेनिफिट्स EPF मेंबरशिप के 12 महीने पूरे होने पर मिलते हैं और इससे सिस्टम एम्प्लॉई के लिए ज़्यादा फ्रेंडली हो गया है।

तीन सरलीकृत निकासी श्रेणियाँ

ज़्यादा अलग-अलग विड्रॉल कारणों को अब तीन आसानी से समझ में आने वाली कैटेगरी में मिला दिया गया है, जो हैं,

- आवश्यक आवश्यकताएं
- आवास की ज़रूरतें
- विशेष परिस्थितियाँ

ऑटो-सेटलमेंट की लिमिट बढ़ाकर ₹5 लाख की गई

ऑटोमैटिक ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग की लिमिट भी ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, इससे इस रकम से कम के एलिजिबल क्लेम बिना किसी मैनुअल वेरिफिकेशन के सेटल किए जा सकते हैं।

तीन नई EPF निकासी श्रेणियां

1. ज़रूरी ज़रूरतें

इस कैटेगरी में ज़रूरी पर्सनल और फ़ैमिली ज़रूरतें शामिल हैं।

चिकित्सा के खर्चे

मेंबर्स अपने या अपने परिवार के करीबी सदस्यों के इलाज के लिए निकाले जा सकने वाले बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं (ज़रूरी 25% बैलेंस रखना होगा)। मेडिकल क्लेम की संख्या पर कोई रोक नहीं है।

शिक्षा

कर्मचारी अपनी EPF मेंबरशिप के दौरान पढ़ाई से जुड़े 10 पैसे तक निकाल सकते हैं। एलिजिबल मेंबर 12 महीने की सर्विस पूरी करने के बाद निकाले जा सकने वाले बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं।

शादी

सदस्य अपने करियर के दौरान शादी के खर्च के लिए पांच बार तक पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यह एलिजिबिलिटी शर्तों पर निर्भर करता है।

2. आवास से संबंधित ज़रूरतें

कर्मचारी अपनी EPF सेविंग्स निकाल सकते हैं,

- भूमि क्रय करना
- घर खरीदना
- घर निर्माण
- घर का नवीनीकरण
- गृह ऋण चुकौती

मेंबर्स अपनी EPF मेंबरशिप के दौरान 12 महीने की सर्विस पूरी होने के बाद पांच बार तक हाउसिंग एडवांस भी क्लेम कर सकते हैं।

3. विशेष परिस्थितियाँ

इस कैटेगरी में ऐसी स्थितियाँ शामिल हैं,

- वित्तीय कठिनाई
- कारखाने बंद
- EPFO सेंट्रल बोर्ड द्वारा घोषित इमरजेंसी

एलिजिबल मेंबर हर फाइनेंशियल ईयर में कुल दो बार तक पैसे निकाल सकते हैं।

नए 25% मिनिमम बैलेंस नियम को समझना

EPF स्कीम 2026 के तहत बड़े सुधारों में से एक ज़रूरी रिटायरमेंट सेविंग्स प्रोटेक्शन सिस्टम की शुरुआत है।

कर्मचारी किसी सर्विस में काम करते समय अपना पूरा EPF बैलेंस नहीं निकाल सकते।

उदाहरण

अगर आपका कुल EPF बैलेंस ₹4 लाख है,

- EPF में रहने के लिए मिनिमम बैलेंस: ₹1 लाख (25%)
- विड्रॉल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट: ₹3 लाख (75%)

बचा हुआ 25% हिस्सा रिटायरमेंट या किसी फ़ाइनल सेटलमेंट तक EPF पर ब्याज़ कमाता रहता है।

ईपीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

सदस्य EPFO सदस्य ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से अपने ऑनलाइन दावे जमा कर सकते हैं।

स्टेप 1

अपने पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें,

- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन)
- पासवर्ड
- कॅप्चा

चरण दो

वेरिफ़ाई करें कि आपका KYC पूरा हो गया है।

और पक्का करें कि नीचे दी गई चीज़ें मंज़ूर हैं,

- आधार
- कड़ाही
- बैंक खाता

चरण 3

जाओ,

ऑनलाइन सर्विसेज़ → क्लेम (फॉर्म 31, 19, 10C और 10D)

चरण 4

यूज़र का रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट वेरिफ़ाई करें।

चरण 5

PF एडवांस (फॉर्म 31) चुनें।

चरण 6

विड्रॉल कैटेगरी चुनें और अपनी एलिजिबल विड्रॉल लिमिट के अंदर टोटल ज़रूरी अमाउंट डालें।

चरण 7

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए आधार OTP का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट करें।

एक बार वेरिफ़ाई हो जाने पर , आपका ऑनलाइन क्लेम सबमिट कर दिया जाएगा।

बेरोज़गारी और फ़ाइनल विड्रॉल के नियम

इन बदले हुए EPF नियमों में नौकरी छोड़ने के बाद पैसे निकालने के बारे में भी साफ़ किया गया है।

एक महीने की बेरोज़गारी के बाद

कर्मचारी अपने EPF बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं।

12 महीने की लगातार बेरोज़गारी के बाद
बाकी 25% भी फाइनल सेटलमेंट के ज़रिए निकाला जा सकता है।
पूर्ण ईपीएफ निकासी
सदस्य इन मामलों में अपने EPF कॉर्पस का कुल 100% निकाल सकते हैं, जैसे,

- सेवानिवृत्ति (आयु 55-58, जैसा लागू हो)
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)
- स्थायी विकलांगता
- स्थायी विदेशी प्रवास

नए EPFO 3.0 सुधारों के फ़ायदे
EPFO के नए सुधारों से कर्मचारियों को कई फ़ायदे मिलेंगे,

- ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट तेज़ी से होगा।
- इससे आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन के ज़रिए पेपरवर्क कम हो जाएगा।
- सिर्फ़ एक साल की सर्विस के बाद PF सेविंग्स तक आसान एक्सेस।
- ₹5 लाख की ज़्यादा ऑटोमैटिक प्रोसेसिंग लिमिट।
- आसान विड्रॉल नियम।
- ज़रूरी बैलेंस बनाए रखने से रिटायरमेंट सेविंग्स की बेहतर सुरक्षा।

भारत और न्यूज़ीलैंड ने 10 समझौतों पर साइन किए, 2030 के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोडमैप लॉन्च किया

भारत और न्यूज़ीलैंड ने 2030 के लिए एक बड़ा रोडमैप लॉन्च करके और डिफेंस , ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर और साइंटिफिक रिसर्च जैसे अलग-अलग एरिया में सहयोग के लिए कुल 10 एग्रीमेंट और MoU पर साइन करके अपने रिश्ते को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया है। माननीय PM मोदी के न्यूज़ीलैंड के ऑफिशियल दौरे के दौरान की गई यह घोषणा, ट्रेड और कल्चरल रिश्तों को मज़बूत करने के लिए दोनों देशों के कमिटमेंट को दिखाती है।

न्यूजीलैंड और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी: एक नया चरण
दोनों देशों ने भारत-न्यूज़ीलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाकर ऑफिशियली अगला कदम उठाया है।
दोनों देश अब 2030 तक के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोडमैप को फाइनल करने के प्रोसेस में हैं, जिसमें कई ज़रूरी एरिया में एक्टिविटीज़ की आउटलाइन दी गई है, जैसे,

- रक्षा और सुरक्षा
- व्यापार और निवेश
- समुद्री साझेदारी
- कृषि
- पर्यटन
- खेल
- संस्कृति
- शिक्षा
- वैज्ञानिक सहयोग
- वैश्विक सहयोग

यह रोडमैप भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग का रास्ता बनाएगा।

यात्रा के दौरान साइन किए गए 10 समझौतों की लिस्ट

1. रक्षा मंत्रालय और न्यूज़ीलैंड रक्षा बल के बीच समुद्री सहयोग पर समझौता ज्ञापन
2. भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के मामलों में सहयोग से जुड़ा इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट
3. इंडियन नेवी और न्यूज़ीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के प्रोविज़न से जुड़ा अरेंजमेंट
4. भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच काउंटर-टेररिज़्म पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का इंतज़ाम
5. नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया और न्यूज़ीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (NEMA) के बीच सहयोग ज्ञापन
6. भारत के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन
7. भारत के पर्यटन मंत्रालय और न्यूज़ीलैंड के व्यापार, नवाचार और रोज़गार मंत्रालय के बीच पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन
8. भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त खेल कार्य योजना
9. गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) के डेवलपमेंट के लिए NMHC और न्यूज़ीलैंड मैरीटाइम म्यूज़ियम के बीच मेमोरेंडम ऑफ़ अरेंजमेंट।
10. भारत के संस्कृति मंत्रालय और न्यूजीलैंड के संस्कृति और विरासत मंत्रालय के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर व्यवस्था

यात्रा के दौरान की गई घोषणाएँ

- भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी और 2030 के लिए रोडमैप
- 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके NZ$7 बिलियन या ₹35,000 करोड़ करना
- समुद्री सुरक्षा संवाद स्थापित करना
- न्यूजीलैंड ने इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) के तहत मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रायोरिटी पिलर के तौर पर नॉमिनेट किया है।
- न्यूजीलैंड ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल हो रहा है
- कीवीफ्रूट एक्शन प्लान की शुरुआत और नागालैंड और उत्तराखंड में कीवीफ्रूट के लिए 2 सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना
- नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR), गोवा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, NZ के बीच MoU
- कुंडली (NIFTEM-K) और मैसी यूनिवर्सिटी, न्यूजीलैंड के बीच MoU

राष्ट्रीय समाचार

- भारत ने गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के नेतृत्व में गुवाहाटी, असम में BRICS ड्रग-रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की । विस्तारित 11-सदस्यीय BRICS के प्रतिनिधियों ने सिंथेटिक ड्रग्स , डार्कनेट ट्रैफिकिंग , न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंस (NPS) और क्रिप्टोकरेंसी-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग सहित चुनौतियों पर चर्चा की । भारत ने नारकोटिक्स कंट्रोल 2026–2029 पर अपना विज़न डॉक्यूमेंट पेश किया , जिसमें टेक्नोलॉजी-ड्रिवन जांच , सीमा निगरानी , खुफिया जानकारी साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ज़ोर दिया गया। शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नेटवर्क के खिलाफ समन्वित वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त घोषणा को अपनाने की उम्मीद है ।

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत भारत ने 104 करोड़ लिंक्ड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड पार कर लिए हैं , जो 93 करोड़ से ज़्यादा ABHA अकाउंट से जुड़े हैं । आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) एक 14-डिजिट की डिजिटल हेल्थ ID है जो मरीज़ों को हॉस्पिटल , डॉक्टर , लैब , फार्मेसी और इंश्योरेंस प्रोवाइडर से सुरक्षित रूप से जोड़ती है । यह पहल पेपरलेस हेल्थकेयर को मुमकिन बनाती है , पूरी मेडिकल हिस्ट्री को सुरक्षित रखती है और इलाज की कंटिन्यूटी में सुधार करती है। सरकार का मकसद देश भर में हेल्थकेयर सुविधाओं को इंटीग्रेट करके डिजिटल पब्लिक हेल्थ इकोसिस्टम को बढ़ाना है , ताकि सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित , आसान और कुशल डिजिटल हेल्थ सर्विस पक्की हो सके।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत गुजरात के साणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) फैसिलिटी का उद्घाटन किया । यह फैसिलिटी चिप पैकेजिंग , असेंबली , टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस में मदद करके भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करती है। भारत , जापान और थाईलैंड के साथ मिलकर डेवलप की गई यह फैसिलिटी शुरू में हर साल 20 करोड़ सेमीकंडक्टर यूनिट बनाएगी , जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ यूनिट करने का प्लान है । यह प्रोजेक्ट हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है , इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और भारत के ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने के सपने को पूरा करता है ।
- भारत ने 2025-26 के दौरान 125 नए जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग रजिस्टर किए, जिससे रजिस्टर्ड GI प्रोडक्ट्स की कुल संख्या 822 हो गई । मध्य प्रदेश 26 रजिस्ट्रेशन के साथ सबसे आगे रहा , उसके बाद पश्चिम बंगाल , हिमाचल प्रदेश और झारखंड का नंबर रहा । नए रजिस्ट्रेशन में पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट , खेती के प्रोडक्ट्स , आदिवासी विरासत और देसी ज्ञान शामिल हैं , जिससे एक्सपोर्ट और मार्केट वैल्यू को बेहतर बनाते हुए क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखने में मदद मिलती है। सभी GI रजिस्ट्रेशन में हैंडीक्राफ्ट का हिस्सा 53% और खेती के प्रोडक्ट्स का 31% है । यह पहल असली क्षेत्रीय प्रोडक्ट्स की सुरक्षा को मज़बूत करती है और भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत को बढ़ावा देती है।
- ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स (GPI) 2026 में भारत 197 देशों में 125वें नंबर पर रहा , जबकि उसे अब तक का सबसे ज़्यादा 45.1 स्कोर मिला है। ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस का पब्लिश किया गया यह इंडेक्स मोबिलिटी , क्वालिटी ऑफ़ लिविंग और इन्वेस्टमेंट के मौकों के आधार पर पासपोर्ट को इवैल्यूएट करता है । मोबिलिटी में भारत 136वें , क्वालिटी ऑफ़ लिविंग में 118वें और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल में 94वें नंबर पर रहा । भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को अभी लगभग 26 जगहों पर वीज़ा-फ्री या वीज़ा-ऑन-अराइवल एक्सेस मिलता है , जबकि कई बड़े देशों के लिए वीज़ा अभी भी ज़रूरी है। स्वीडन ने 2026 की रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की।
- एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) ने जम्मू और कश्मीर से यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) को प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज़ प्लम का पहला एक्सपोर्ट किया । शोपियां और पुलवामा से मंगाया गया एक -मीट्रिक टन का शिपमेंट अबू धाबी और दुबई पहुंचा। बताया जा रहा है कि किसानों को घरेलू बाज़ारों के मुकाबले चेरी से लगभग 60% ज़्यादा और प्लम से 120% ज़्यादा रिटर्न मिला। इस पहल का मकसद भारत के ताज़े फलों के एक्सपोर्ट को बढ़ाना , किसानों की इनकम में सुधार करना, बागवानी एक्सपोर्ट को मज़बूत करना और जम्मू और कश्मीर को एक लीडिंग प्रीमियम फल-एक्सपोर्टिंग इलाका बनाना है।
- केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस के मौके पर एक कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाने और दो साल के अंदर भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म को 500 शहरों तक बढ़ाने का ऐलान किया । इंश्योरेंस कंपनी का मकसद कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करना , फाइनेंशियल इनक्लूजन को बढ़ावा देना और इंश्योरेंस एक्सेस को बेहतर बनाना है। कोऑपरेटिव मॉडल के तहत काम करने वाली भारत टैक्सी के अभी 6.37 लाख ड्राइवर और 35.77 लाख कस्टमर हैं। यह पहल ऑर्गेनिक खेती , PACS के ज़रिए एंटरप्रेन्योरशिप और देश भर में कोऑपरेटिव की अगुवाई में आर्थिक विकास और रोज़गार पैदा करने को भी बढ़ावा देती है ।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जिसे HPCL और राजस्थान सरकार ने ₹79,450 करोड़ के निवेश से बनाया है। इस फैसिलिटी में 9 MMTPA क्रूड रिफाइनिंग कैपेसिटी और 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी है , जो फ्यूल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाती है। यह प्रोजेक्ट पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट को कम करेगा , एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेगा , रोजगार पैदा करेगा और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। यह पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क को भी बढ़ावा देता है , जिससे पश्चिमी राजस्थान एक बड़ा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (NHM), मिजोरम विश्वविद्यालय को , जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत भारत के 21वें नामित भंडार के रूप में नामित किया है । राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) द्वारा अनुशंसित , भंडार प्रमाणित जैविक नमूनों को संरक्षित करता है , प्रजातियों की पहचान का समर्थन करता है , और जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करता है। इंडो-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित , संग्रहालय में पौधे, कवक, कीड़े, सरीसृप, उभयचर और मछलियों को कवर करने वाले 500 से अधिक नमूने हैं । मान्यता जैव विविधता प्रलेखन , पारिस्थितिक बहाली, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षेत्रीय संरक्षण संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ाती है
- केंद्र सरकार ने सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज़ (CABs) के कर्मचारियों को दो नए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लाइफ-साइकिल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिए हैं । LC -75 हाई फंड लंबे समय में पैसा बनाने के लिए 75% तक इक्विटी एक्सपोज़र देता है, जबकि एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड लगभग 50% इक्विटी एक्सपोज़र देता है, जिससे 45 साल की उम्र के बाद रिस्क धीरे-धीरे कम होता है । पहले ये ऑप्शन सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए थे, ये रिटायरमेंट प्लानिंग को बेहतर बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, पोर्टफोलियो को पर्सनल फाइनेंशियल लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं, और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) प्लेटफॉर्म के ज़रिए NPS का आकर्षण बढ़ाते हैं ।

- तमिलनाडु में कामराजार पोर्ट लिमिटेड (KPL) विशाखापत्तनम पोर्ट के बाद भारत का दूसरा पोर्ट बन गया है, जिसने ₹440 करोड़ के कैपिटल ड्रेजिंग फेज़ VI प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद 18-मीटर का ऑपरेशनल ड्राफ्ट हासिल किया है। इस अपग्रेड से 1,70,000 DWT तक के पूरी तरह से भरे हुए केपसाइज़ जहाजों को हैंडल किया जा सकेगा, जिससे कार्गो कैपेसिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार होगा। बेहतर चैनल डेप्थ, बर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और नेविगेशनल सुविधाओं से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, जहाज का टर्नअराउंड टाइम बेहतर होगा, EXIM ट्रेड मजबूत होगा और भारत की ग्लोबल मैरीटाइम कॉम्पिटिटिवनेस काफी बढ़ेगी।
- मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र ने नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल (NWDT) अवॉर्ड के तहत सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और इंदिरा सागर प्रोजेक्ट से जुड़े लंबे समय से रुके हुए फाइनेंशियल झगड़ों को सुलझाने के लिए एक अहम एग्रीमेंट पर साइन किए। इस एग्रीमेंट में हिस्सा लेने वाले राज्यों के बीच कॉस्ट-शेयरिंग, रिहैबिलिटेशन खर्च, ज़मीन का मुआवज़ा, ब्याज की देनदारियों और पेंडिंग ड्यूज़ को शामिल किया गया है। अमित शाह और सीआर पाटिल की मौजूदगी में साइन किए गए इस एग्रीमेंट से कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म मज़बूत होता है, इंटर-स्टेट वॉटर गवर्नेंस में सुधार होता है, और नर्मदा बेसिन में सस्टेनेबल सिंचाई, हाइड्रोपावर जेनरेशन और पीने के पानी के मैनेजमेंट को सपोर्ट मिलता है।
- सरकार ने पांच साल में ₹60,000 करोड़ के निवेश के साथ अपग्रेडेड ITIs (PM-SETU) स्कीम के ज़रिए प्रधानमंत्री स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन को पूरे देश में लागू करने की मंज़ूरी दी है। इस पहल से अपग्रेडेड लैबोरेटरी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड इक्विपमेंट, बदले हुए करिकुलम और बेहतर प्लेसमेंट सपोर्ट के ज़रिए 1,000 सरकारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITIs) को मॉडर्न बनाया जाएगा। यह हब-एंड-स्पोक मॉडल का इस्तेमाल करके पांच नेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (NCoEs) भी बनाएगा। इस स्कीम का मकसद इंडस्ट्री के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाना, वोकेशनल एजुकेशन को मज़बूत करना, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना और इंडस्ट्री-एकेडेमिया कोलेबोरेशन को बढ़ावा देना है।
- ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ट्राइबएक्स लॉन्च किया है, जो ट्राइबल आर्ट्स, कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए इंडिया का पहला डेडिकेटेड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। भुवनेश्वर में जुएल ओराम ने इसका उद्घाटन किया। यह प्लेटफॉर्म अभी 20 फ्री सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर करता है और इसे 100 से ज़्यादा कोर्स तक बढ़ाने का प्लान है। यह ट्राइबल स्टडीज़, म्यूज़ियोलॉजी, टेक्सटाइल और सस्टेनेबल लाइवलीहुड में UGC से मान्यता प्राप्त पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम भी शुरू करता है। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ एक MoU के सपोर्ट से, ट्राइबएक्स डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, नौकरी के मौके और इंडिया की रिच ट्राइबल हेरिटेज के बचाव को बढ़ावा देता है।
- IIM बैंगलोर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत इंडोनेशिया के मलंग में सिंघासरी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) में अपने पहले विदेशी कैंपस की घोषणा की। PT इंटेलीजेंसिया के साथ एक MoU के ज़रिए डेवलप किया गया। ग्रहतमा के अनुसार, यह प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और लीडरशिप प्रोग्राम से शुरू होगा, जिसके बाद फुल मैनेजमेंट डिग्री कोर्स होंगे। एकेडमिक फोकस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थकेयर मैनेजमेंट, क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी, और ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट शामिल हैं। यह पहल भारत-इंडोनेशिया एजुकेशनल सहयोग को मजबूत करती है और भारतीय हायर एजुकेशन संस्थानों की ग्लोबल मौजूदगी को बढ़ाती है।
- इंडिया BESS मार्केट रिव्यू और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) के लेटेस्ट अनुमानों के मुताबिक, 2035-36 तक भारत की एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत 888 GWh तक पहुँचने का अनुमान है। इस ज़रूरत में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) से 80 GW/321 GWh और पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (PSPs) से 94 GW/567 GWh शामिल हैं। इंस्टॉल्ड BESS कैपेसिटी 2026 तक 10 GWh से ज़्यादा होने की उम्मीद है, जबकि लिथियम-आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग 2030 तक 110 GWh तक पहुँच सकती है। यह विस्तार रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, ग्रिड रिलायबिलिटी और भारत के लॉन्ग-टर्म क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन को सपोर्ट करता है।
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल और FMCG ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) हब बन गया है, जिसमें 180 GCC हैं और 2.72 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स काम करते हैं। वॉलमार्ट, टेस्को, टारगेट, H&M, लॉरियल और लोव्स जैसी बड़ी कंपनियाँ भारत में टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, फाइनेंस और सप्लाई-चेन सेंटर चलाती हैं। GCC में रोज़गार के मामले में बेंगलुरु सबसे आगे है, उसके बाद दिल्ली NCR और हैदराबाद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को तेज़ी से अपनाने से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs), GenAI ऑप्स, MLOps और डेटा एनालिटिक्स में स्पेशलिस्ट्स की डिमांड बढ़ी है, जिससे ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब के तौर पर भारत की जगह मज़बूत हुई है।
- भारत ने नई दिल्ली में 13वीं ASEAN-इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट (AITIGA) जॉइंट कमिटी मीटिंग होस्ट की ताकि इंडिया-ASEAN ट्रेड पैक्ट के रिव्यू में तेज़ी लाई जा सके। सभी 10 ASEAN सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने रीजनल ट्रेड को मज़बूत करने के लिए कस्टम्स प्रोसीजर, ट्रेड फैसिलिटेशन, मार्केट एक्सेस और रूल्स ऑफ़ ओरिजिन पर चर्चा की। नितिन कुमार यादव और मस्तुरा अहमद मुस्तफा की को-चेयर में हुई इस मीटिंग में पेंडिंग बातचीत के लिए टाइम-बाउंड काम दिए गए। इंडिया के ग्लोबल ट्रेड में ASEAN का हिस्सा लगभग 11% है, और 2025-26 तक दोनों देशों का ट्रेड USD 128 बिलियन तक पहुँच जाएगा।
- जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ़ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स (JIM & WS) ने लद्दाख में माउंट ख्याम त्सो मैसिफ़ पर एक माउंटेनियरिंग अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। टीम ने खराब मौसम के बावजूद पीक Pt 5901 m, पीक Pt 6090 m, पीक Pt 5944 m, और आखिर में माउंट ख्याम-III (6,018 m) पर चढ़ाई की। अभियान के लीडर कर्नल हेम चंद्र सिंह ने 5,600 मीटर से पहली बार पैराग्लाइडिंग की उड़ान भी भरी। इस अभियान ने भारत की माउंटेनियरिंग में महारत, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और दूर-दराज के हिमालयी इलाकों को एक्सप्लोर करने के कमिटमेंट को दिखाया।

- जयपुर ने हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में दुनिया भर में 6th पोजीशन हासिल की , और ग्लोबल टॉप टेन में अकेला भारतीय शहर बन गया। यह रैंकिंग गवर्नेंस , हेल्थकेयर , एजुकेशन , मोबिलिटी , एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी , इनोवेशन और क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ में बेहतरीन काम को पहचान देती है। जयपुर की सफलता कल्चरल हेरिटेज को बचाने और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट , बेहतर सिविक सुविधाओं, टूरिज़्म, हैंडीक्राफ्ट और इकोनॉमिक मौकों को बढ़ावा देने के बीच इसके बैलेंस को दिखाती है । यह पहचान सस्टेनेबल , रहने लायक और सिटिज़न-सेंट्रिक अर्बन डेवलपमेंट पर भारत के बढ़ते ज़ोर को दिखाती है ।
- एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने CITES 2.01 (सेंट्रलाइज्ड IT इनेबल्ड सर्विसेज़) लॉन्च किया , जिससे लगभग 340 मिलियन मेंबर अकाउंट एक यूनिफाइड नेशनल प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट हो गए। मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू किया गया यह सिस्टम एक ही पोर्टल के ज़रिए सेंट्रलाइज्ड क्लेम प्रोसेसिंग , रियल-टाइम ट्रैकिंग और तेज़ डिजिटल सर्विसेज़ को इनेबल करता है। FY2025–26 के लिए EPF इंटरेस्ट रेट 8.25% बना हुआ है , जबकि ऑटो-सेटलमेंट लिमिट ₹1 लाख से बढ़कर ₹5 लाख हो गई है। भविष्य के फीचर्स में UPI-बेस्ड PF विड्रॉल और PF बैलेंस का 75% तक विड्रॉल शामिल है ।
- हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत का 42वां डेजिग्नेटेड ड्रग इंपोर्ट पोर्ट नोटिफाई किया है । यह नोटिफिकेशन दवाओं के लिए एक एक्स्ट्रा रेगुलेटेड एंट्री पॉइंट देकर देश के फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) से सलाह के बाद जारी किया गया यह फैसला हेल्थकेयर लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाता है , सप्लाई चेन की एफिशिएंसी बढ़ाता है , मौजूदा पोर्ट्स पर कंजेशन कम करता है, और भारत के बढ़ते फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सपोर्ट करते हुए रेगुलेटरी ओवरसाइट को मजबूत करता है।
- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सस्टेनेबल खेती और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए PRAGATI (रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, ग्रोथ, एग्री-एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन को बढ़ावा देना) पहल शुरू की । इस प्रोग्राम का मकसद रीजेनरेटिव खेती , डिजिटल टेक्नोलॉजी , मिट्टी की टेस्टिंग , मशीनीकरण और फाइनेंशियल लिटरेसी के ज़रिए 20,000 एग्री - एंटरप्रेन्योर को डेवलप करना और 20 लाख छोटे और मार्जिनल किसानों को फायदा पहुंचाना है । शुरुआत में आठ राज्यों को कवर करते हुए, इस पहल को पेप्सिको फाउंडेशन , SBI फाउंडेशन और गेट्स फाउंडेशन जैसे संगठनों का सपोर्ट है , जो क्लाइमेट-रेसिलिएंट और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन खेती को बढ़ावा देते हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के साथ , योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स गए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) के रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। 9वीं सदी में बना यह UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट , इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स है, जो त्रिमूर्ति — शिव , विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है । यह रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट सदियों पुराने भारत-इंडोनेशिया कल्चरल रिश्तों का प्रतीक है , हेरिटेज कंज़र्वेशन को मज़बूत करता है, और ऐतिहासिक स्मारकों और साझा सभ्यता की परंपराओं को बचाने में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- भारत ने सस्टेनेबल डीप-सी फिशिंग को बढ़ावा देने , ब्लू इकॉनमी को मज़बूत करने और मछुआरों की रोज़ी-रोटी को बेहतर बनाने के लिए लेटर ऑफ़ ऑथराइज़ेशन (LoA) सिस्टम लॉन्च किया। यह फ्रेमवर्क एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) और हाई सीज़ में रेगुलेटेड फिशिंग की इजाज़त देता है, जिससे कोस्टल फिशरीज़ पर दबाव कम होता है और सीफ़ूड एक्सपोर्ट बढ़ता है। फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन (FFPOs) और कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करते हुए, यह पहल मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट को बढ़ाती है। इसके साथ ही, ओडिशा ने फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्वापार्क, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ और मॉडर्न मार्केट डेवलप करने के लिए ₹2,295.45 करोड़ के साथ डीप सी फिशिंग मिशन 2026–2036 लॉन्च किया , जिससे भारत की मरीन इकॉनमी और सस्टेनेबल फिशरीज़ ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा।
- जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (GSI) ने कर्नाटक के गुंडलूपेट में थोरियम वाले डिपॉज़िट खोजे हैं , जो लगभग 700 एकड़ में फैले हैं , जिसमें से 20 एकड़ माइनिंग के लिए पहचाने गए हैं। मोनाज़ाइट में पाए जाने वाले इन डिपॉज़िट में थोरियम , रेयर अर्थ एलिमेंट्स और यूरेनियम होते हैं। थोरियम से यूरेनियम-233 बन सकता है , जो इसे भविष्य का एक ज़रूरी न्यूक्लियर फ्यूल बनाता है। भारत के पास पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े थोरियम रिज़र्व में से एक है। यह खोज स्ट्रेटेजिक मिनरल सिक्योरिटी को मज़बूत करती है, भविष्य के एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टरों को सपोर्ट करती है , और रिसोर्स असेसमेंट को बेहतर बनाती है। मिनिस्ट्री ऑफ़ माइंस के तहत काम करते हुए , GSI भारत के लॉन्ग-टर्म न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन जारी रखे हुए है ।
- इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (ICMR) हिमाचल प्रदेश के केलांग में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर बनाएगा । यह सेंटर एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी , एक्यूट माउंटेन सिकनेस (AMS) , HAPE , HACE , डिजास्टर मेडिसिन, क्लाइमेट-सेंसिटिव बीमारियों, मैटरनल हेल्थ, न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ पर रिसर्च करेगा । यह टेलीमेडिसिन , ड्रोन-बेस्ड हेल्थकेयर , डिजिटल सर्विलांस का इस्तेमाल करेगा और DRDO , AFMS और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करेगा। 2,500 मीटर से ऊपर मौजूद यह फैसिलिटी एडवांस्ड माउंटेन मेडिसिन के ज़रिए भारत के हिमालयी और बॉर्डर इलाकों में हेल्थकेयर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और साइंटिफिक रिसर्च को मज़बूत करेगी।
- AISHE रिपोर्ट्स 2022–23 और 2023–24 में हायर एजुकेशन में रिकॉर्ड 4.5 करोड़ एनरोलमेंट का पता चला , जो 2014–15 से 31.5% ज़्यादा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) बढ़कर 30 हो गया , जबकि 31.2 के GER के साथ महिलाओं का एनरोलमेंट 2.24 करोड़ तक पहुँच गया । जेंडर पैरिटी इंडेक्स (GPI) लगातार सातवें साल 1.08 से ऊपर रहा । STEM एनरोलमेंट एक करोड़ को पार कर गया , जिसमें 44% महिलाएँ स्टूडेंट थीं। फैकल्टी की संख्या 17.32 लाख तक पहुँच गई, जो NEP 2020 के तहत इनक्लूसिव, क्वालिटी-ड्रिवन हायर एजुकेशन और देश भर में बढ़ी हुई पहुँच की दिशा में हुई प्रोग्रेस को दिखाता है ।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयंबटूर के WII-SACON में इंसान-जानवरों के बीच टकराव पर सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया । यह सेंटर इंसान-जानवरों के बीच टकराव को सुलझाने के लिए रिसर्च, पॉलिसी सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग और इनोवेशन के लिए एक नेशनल हब के तौर पर काम करेगा । यह टकराव कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सैटेलाइट मैपिंग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेगा । नेशनल इंसान-जानवरों के बीच टकराव पोर्टल और जंगली जानवरों के बीच टकराव पर एक स्टेटस रिपोर्ट भी लॉन्च की गई, जो साइंटिफिक कंज़र्वेशन, सबूतों पर आधारित पॉलिसी बनाने और जंगली जानवरों और इंसानी समुदायों दोनों की सुरक्षा को बढ़ावा देगी ।
- NABARD ने 28 नए प्रोडक्ट्स के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी , जिससे उसके कुल सपोर्टेड GI प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़कर 176 हो गई । नए रजिस्टर्ड आइटम्स में कई राज्यों के हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम टेक्सटाइल्स, बांस के क्राफ्ट्स, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स ऑफ गुड्स एक्ट, 1999 के तहत , GI खास इलाकों से जुड़े प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। NABARD ने GI फैसिलिटेशन सेंटर्स और एक GI स्टोर भी बनाए हैं , जिससे 13,000 से ज़्यादा कारीगरों को फायदा हुआ है और 50,000 से ज़्यादा सीधे नौकरी के मौके बने हैं ।
- यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अल्कोहल-बेस्ड मेडिसिनल फॉर्मूलेशन के रेगुलेशन को मज़बूत करने के लिए ड्रग्स रूल्स, 1945 में बदलाव किया है । 30 ml से ज़्यादा क्वांटिटी में 12% v/v एथिल अल्कोहल वाले प्रोडक्ट्स के लिए अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सेल लाइसेंस की ज़रूरत होगी । इन दवाओं को शेड्यूल H1 में शामिल किया गया है , जिससे ये सिर्फ़ प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं बन गई हैं और इनके लिए फार्मेसी रिकॉर्ड ज़रूरी हैं। बदले हुए नियमों का मकसद जनवरी 2027 से दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकना है, साथ ही सही मेडिकल इस्तेमाल पक्का करना है ।
- डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट्स (DoP) और TRAI ने 5.68 लाख गांवों को कवर करते हुए भारत का सबसे बड़ा रूरल टेलीकॉम नेटवर्क परफॉर्मेंस सर्वे करने के लिए एक MoU साइन किया है । एक Android-बेस्ड एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके , ग्रामीण डाक सेवक (GDS) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL की मोबाइल सर्विसेज़ को असेस करेंगे । यह इनिशिएटिव नेटवर्क गैप्स की पहचान करेगा , सर्विस क्वालिटी को इवैल्यूएट करेगा, और एविडेंस-बेस्ड पॉलिसीमेकिंग के लिए डेटा देगा, जिससे डिजिटल इंडिया को मज़बूत करने , रूरल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को गाइड करने में मदद मिलेगी ।

राज्य समाचार

- दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने और पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया है । मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल की घोषणा की, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत, लैब को अपग्रेड करना, सफाई में सुधार , RO पीने के पानी के सिस्टम लगाना , दिव्यांग बच्चों के लिए पहुंच बढ़ाना और ग्रीन कैंपस बनाना शामिल है। यह मिशन शिक्षा विभाग , जिला प्रशासन , CSR पहल , सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी बढ़ावा देता है । मिशन कायाकल्प का मकसद पूरी दिल्ली के छात्रों के लिए सुरक्षित , सबको साथ लेकर चलने वाला , मॉडर्न और हाई-क्वालिटी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर देना है ।
- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से रोड कनेक्टिविटी में रुकावट आने के बाद लोअर सियांग जिले में बाढ़ से प्रभावित गांवों की मदद के लिए एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर राहत ऑपरेशन शुरू किया। स्काईवन एयरवेज के Mi-172 हेलीकॉप्टर ने पासीघाट से कोयू तक 11.5 मीट्रिक टन PDS चावल , दवाइयां और ज़रूरी सामान पहुंचाया , और चार गंभीर रूप से बीमार मरीजों को इलाज के लिए निकाला । इस ऑपरेशन में कई अलग-थलग गांवों को कवर किया गया और इसमें सिविल एविएशन डिपार्टमेंट , जिला प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शामिल थीं, जिससे यह पता चला कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तेज़ी से मानवीय मदद पहुंचाने में एयर कनेक्टिविटी की अहम भूमिका होती है ।
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इनोवेशन को मज़बूत करने और 2030 तक राज्य की $1 ट्रिलियन इकॉनमी का टारगेट पाने में मदद के लिए स्टार्टअप पॉलिसी 2026 को मंज़ूरी दी । इस पॉलिसी में ₹1,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड , ₹15 लाख की सीड फंडिंग , ₹50 लाख का स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट सपोर्ट , ₹10 लाख के प्रोटोटाइप ग्रांट और ₹2 लाख का सालाना क्लाउड रीइंबर्समेंट शामिल है। AI , मशीन लर्निंग , रोबोटिक्स और एयरोस्पेस स्टार्टअप के लिए खास इंसेंटिव दिए गए हैं , जिसमें ₹100 करोड़ तक का पेशेंट कैपिटल शामिल है । यह पॉलिसी इनक्यूबेटर और कम रिप्रेजेंटेशन वाले एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल सपोर्ट देकर इनक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देती है।
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य को ग्रीन और AI-रेडी डेटा सेंटर्स के लिए ग्लोबल हब बनाने के लिए डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 को मंज़ूरी दी । इस पॉलिसी का मकसद ₹2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लाना और 2 GW डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाना है। यह GPU-बेस्ड टेक्नोलॉजी , टियर III और टियर IV डेटा सेंटर्स के लिए इंसेंटिव और बुंदेलखंड और पूर्वांचल में प्रोजेक्ट्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी देता है । इस पहल से 50,000 कंस्ट्रक्शन जॉब्स और 7,500 ऑपरेशनल जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है , साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, फिनटेक, डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ को मज़बूती मिलेगी।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने केंद्र सरकार से मंज़ूरी मिलने के बाद शाहजहांपुर ज़िले के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंज़ूरी दे दी है। इस फ़ैसले से शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक जुड़ाव को भगवान विष्णु के छठे अवतार , भगवान परशुराम की जन्मभूमि के तौर पर मान्यता मिली है। सरकार ने कहा कि नया नाम इस इलाके की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक पहचान को बेहतर ढंग से दिखाता है। कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, संबंधित विभाग आधिकारिक तौर पर लागू करने के लिए ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करेंगे ।
- सिरसा किन्नू हरियाणा का पहला फल बन गया है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग मिला है , जिससे इसकी खास क्वालिटी और इलाके की पहचान हुई है। चेन्नई की GI रजिस्ट्री ने खारीसुवेरियन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को रजिस्ट्रेशन दिया है । अपने मीठे स्वाद , ज़्यादा जूस , बड़े साइज़ और चमकीले रंग के लिए मशहूर , सिरसा किन्नू को इस इलाके के अच्छे मौसम से फ़ायदा होता है। GI टैग नकल के खिलाफ़ कानूनी सुरक्षा देता है, ब्रांडिंग को मज़बूत करता है, घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँच को बेहतर बनाता है, किसानों की इनकम बढ़ाता है, और हरियाणा को एक ज़रूरी हॉर्टिकल्चर पैदा करने वाले राज्य के तौर पर मज़बूत करता है।

Test Prime By Adda247

ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION

Test. Analyze. Improve. Repeat.

Don't just prepare. Perform.

Test Prime – built only for mock tests.

1,50,000+ Mock Tests

25,000+ Previous Year Papers

800+ Exam Covered

500% Refund on Selection

5 lakh+ Free Quizzes

Daily Free PDFs

Top Alerts Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- Multilingual
- Detailed Solution
- Strong and Weak Areas
- All India Rankings

- Safe & Reliable
- Trusted by Lakhs of Aspirants
- Your Success, Our Mission

DOWNLOAD TEST PRIME

Your Success Partner!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

- पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में 3 लाख से ज़्यादा चाय बागान मज़दूरों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना (PMCSPY) के लिए ₹313.3 करोड़ के इम्प्लीमेंटेशन पैकेज को मंज़ूरी दी है। पैकेज में शिक्षा के लिए ₹177 करोड़, हेल्थकेयर के लिए ₹72 करोड़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹63 करोड़ दिए गए हैं, जिसमें 321 मज़दूरों के आराम के लिए शेड भी शामिल हैं। यह योजना उत्तर बंगाल विकास विभाग के ज़रिए स्वास्थ्य विभाग और ज़िला प्रशासन की मदद से लागू की जाएगी, जिससे चाय बागान मज़दूरों की शिक्षा, हेल्थकेयर और रहने की स्थिति में सुधार होगा।
- गुजरात राजवासना और पाठकवाड़ी में साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना पहला हवा से भरा हुआ इनफ्लेटेबल रबर डैम बना रहा है, जिसमें कुल मिलाकर ₹162 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। ऑटोमेटेड SCADA सिस्टम और ड्यूरेबल हाई-टेंसाइल रबर ब्लैडर से लैस, ये डैम सिंचाई, ग्राउंडवाटर रिचार्ज, पानी का स्टोरेज और बाढ़ कंट्रोल को बेहतर बनाएंगे। राजवासना डैम 3,420 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन की सिंचाई करेगा, जबकि पाठकवाड़ी प्रोजेक्ट से लगभग 650 हेक्टेयर ज़मीन को फ़ायदा होगा। लगभग 30 साल की लाइफ के साथ डिज़ाइन किए गए ये डैम कुशल और कम मेंटेनेंस वाले वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट की सुविधा देते हैं।
- त्रिपुरा सरकार ने सभी सरकारी, सरकारी मदद वाले, प्राइवेट स्कूलों और मान्यता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम और जन गण मन का पूरा गायन ज़रूरी कर दिया है। हर स्कूल का दिन राष्ट्रगान से शुरू होगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा, और छात्र और स्टाफ़ सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। यह निर्देश गृह मंत्रालय (MHA) की गाइडलाइंस के अनुसार है और इसे त्रिपुरा मंत्रिपरिषद ने मंज़ूरी दी है। इस पहल का मकसद छात्रों में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और भारत की संवैधानिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- उत्तराखंड ULLAS (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) के तहत भारत का छठा पूरी तरह साक्षर राज्य बन गया। प्रोग्राम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020। गवर्नर से मंज़ूर इस कामयाबी ने उत्तराखंड को मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कामयाबी का क्रेडिट सबकी भागीदारी को दिया और डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, कंटिन्यूइंग एजुकेशन और लाइफलॉन्ग लर्निंग के लिए अपना वादा दोहराया, जिससे पूरे राज्य में सबको साथ लेकर चलने वाले एजुकेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
- AISHE के अनुसार, तमिलनाडु ने 2023-24 के दौरान हायर एजुकेशन में भारत का सबसे ज़्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (GER) 52.3% दर्ज किया, जो 30% के नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। महिलाओं का GER 53.1% तक पहुँच गया, जो लगातार तीसरे साल पुरुषों के 51.6% से ज़्यादा है। लगभग 35.8 लाख युवाओं ने हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट किया, जिन्हें 2,18,656 फैकल्टी मेंबर का सपोर्ट मिला, जो भारत के टीचिंग वर्कफोर्स का 12.6% है। यह उपलब्धि एजुकेशनल एक्सेस, महिलाओं की भागीदारी, क्वालिटी इंस्टीट्यूशन और इनक्लूसिव डेवलपमेंट में लगातार प्रोग्रेस को दिखाती है, जिससे देश भर में हायर एजुकेशन में तमिलनाडु की लीडरशिप मज़बूत हुई है।
- आंध्र प्रदेश सरकार UDAN स्कीम के तहत श्रीकाकुलम में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएगी, जिससे नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। AAI और APADC के बीच एक एग्रीमेंट के बाद एयरपोर्ट दो फेज़ में 1,383 एकड़ में बनाया जाएगा। मॉडिफाइड UDAN 2026–2036 के तहत, ₹28,840 करोड़ के खर्च के साथ, भारत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का प्लान बना रहा है। यह प्रोजेक्ट आने वाले भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरा करता है, हालांकि लोकल स्टेकहोल्डर्स और विरोधी ग्रुप्स द्वारा बताए गए उद्दानम नारियल उगाने वाले इलाके में खेती पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
- गुजरात सरकार ने AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और हाइपरस्केल डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए विकसित गुजरात – डेटा सेंटर पॉलिसी 2026–29 पेश की। यह पॉलिसी कैपिटल सब्सिडी, पावर टैरिफ सपोर्ट, SGST रीइंबर्समेंट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट, स्टाम्प ड्यूटी के फायदे और आसान अप्रूवल देती है। 69 GW इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, लगभग 47 GW रिन्यूएबल एनर्जी, धोलेरा SIR, GIFT सिटी और मजबूत लॉजिस्टिक्स के साथ, गुजरात का मकसद भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनना है। यह पहल डिजिटल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट को मजबूत करते हुए सुरक्षित डेटा प्रोसेसिंग की बढ़ती मांग को पूरा करती है।
- दिल्ली सरकार 1 अगस्त 2026 से DTC और क्लस्टर बसों में फ्री सफ़र करने वाली महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू करेगी। यह कार्ड पेपर वाले पिंक टिकट की जगह लेगा। इसका फ़ायदा उठाने के लिए महिलाओं को बस में चढ़ते समय स्मार्ट कार्ड पर टैप करना होगा। एनरोलमेंट के लिए लगभग 50 रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं। इस पहल का मकसद फ्री बस सफ़र को डिजिटाइज़ करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, पेपर का इस्तेमाल कम करना, टिकट वेरिफ़िकेशन को आसान बनाना, ऑपरेशनल एफ़िशिएंसी बढ़ाना और स्कीम का गलत इस्तेमाल रोकना है।
- झारखंड सरकार ने राज्य को AI-ड्रिवन टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस हब में बदलने के लिए AI पॉलिसी 2026–31 लॉन्च की। पॉलिसी में ₹10,000 करोड़ से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ₹1,150 करोड़ के पब्लिक इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव है, 50+ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs) बनाए जाएंगे, 1,000 AI स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा, और एक लाख से ज़्यादा AI-इनेबल्ड जॉब्स पैदा की जाएंगी। मुख्य पहलों में चीफ मिनिस्टर डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP), हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम (HNVS), और क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (CMAS) शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय मामले

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए 6-11 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का छह दिन का डिप्लोमैटिक दौरा शुरू किया। इंडोनेशिया में, वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो से मिलेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रिव्यू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानसे के साथ चर्चा डिफेंस, ट्रेड, ज़रूरी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर फोकस करेगी। न्यूजीलैंड दौरे में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आर्थिक सहयोग पर बातचीत शामिल है। यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, MAHASAGAR विजन और एक फ्री और इनक्लूसिव इंडो-पैसिफिक के प्रति कमिटमेंट को मजबूत करता है।

- भारत जिनेवा में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ और पॉलिसी पर UNCTAD इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ़ एक्सपर्ट्स (IGE) के नौवें सेशन की अध्यक्षता कर रहा है। निधि खरे की लीडरशिप में, यह मीटिंग ग्लोबल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। एक बड़ी हाइलाइट कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए UN प्रिंसिपल्स का लॉन्च है, जिसे दिसंबर 2025 में UN जनरल असेंबली ने अपनाया था। भारत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और AI-पावर्ड ई-जागृति प्लेटफॉर्म जैसी पहल दिखा रहा है, जो डिजिटल कंज्यूमर शिकायत निवारण और इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी में अपनी लीडरशिप को हाईलाइट करता है।
- भारत और इंडोनेशिया ने डिफेंस, ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्पेस, एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट, हेल्थकेयर, ज़रूरी मिनरल्स और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े 14 एग्रीमेंट्स पर साइन करके अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़बूत किया। इंडोनेशिया US$600 मिलियन से ज़्यादा कीमत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल और एस्ट्रा बियॉन्ड-विजुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAMs) खरीदने पर राज़ी हुआ। दोनों देशों ने एक आज़ाद, खुले, सबको साथ लेकर चलने वाले और नियमों पर आधारित इंडो-पैसिफिक के लिए सपोर्ट को फिर से पक्का किया, जिसमें ASEAN सेंट्रलिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंटरनेशनल लॉ और मज़बूत रीजनल सिक्योरिटी पर ज़ोर दिया गया, जिससे दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिश्ते और गहरे हुए।
- भारत और रवांडा ने नई दिल्ली में दूसरी जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी (JDCC) मीटिंग के दौरान डिफेंस संबंधों को मजबूत किया। 2018 के डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के आधार पर, दोनों देशों ने मिलिट्री ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मिलिट्री मेडिसिन और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग को कवर करने वाला एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान अपनाया। रवांडा के डेलीगेशन ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ भी बातचीत की और आर्मी हॉस्पिटल (रेफरल एंड रिसर्च) का दौरा किया। यह मीटिंग आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग को बढ़ाती है, मिलिट्री हेल्थकेयर सहयोग को मजबूत करती है, और अफ्रीकी पार्टनर्स के साथ भारत के बढ़ते स्ट्रेटेजिक जुड़ाव को दिखाती है।
- स्विट्ज़रलैंड ने घोषणा की है कि जिनेवा AI समिट 2027, ITU AI फॉर गुड ग्लोबल समिट के साथ 21-22 जून 2027 को होगा। इस इवेंट में दुनिया के लीडर, रिसर्चर, टेक्नोलॉजी कंपनियां और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन AI गवर्नेंस, इनोवेशन, एथिक्स, AI सेफ्टी और ज़िम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होंगे। पिछले ग्लोबल AI समिट को आगे बढ़ाते हुए, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ह्यूमन-सेंट्रिक, इनक्लूसिव और भरोसेमंद AI को बढ़ावा देना है, साथ ही मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पॉलिसीमेकिंग के लिए ग्लोबल सेंटर के तौर पर जिनेवा की भूमिका को मज़बूत करना है।
- भारत और म्यांमार ने नई दिल्ली में 23वीं नेशनल-लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग की, जिसमें 1,643 km लंबे बॉर्डर पर सुरक्षा का रिव्यू किया गया। दोनों देश इंटेलिजेंस शेयरिंग और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाकर आतंकवाद, बगावत, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, हथियारों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वाइल्डलाइफ क्राइम और साइबर क्राइम के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। चर्चा में कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत-म्यांमार-थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे पर भी बात हुई, जो भारत के पड़ोस को सपोर्ट करता है।
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, OpenAI फ्रंटियर AI सिस्टम्स के लिए नए US डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स फ्रेमवर्क के तहत इवैल्यूएशन पूरा करने के बाद GPT-5.6 को बड़े लेवल पर रोलआउट करने का प्लान बना रहा है। रिव्यू में एडवांस्ड AI मॉडल्स के लिए ओवरसाइट बनाने वाले 2026 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत साइबर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, AI सेफ्टी और गलत इस्तेमाल के रिस्क का असेसमेंट किया गया। यह फ्रेमवर्क साइबर खतरों, गलत जानकारी, मिलिट्री गलत इस्तेमाल और दुश्मन एक्टर्स के खिलाफ सेफगार्ड्स के साथ इनोवेशन को बैलेंस करने की कोशिश करता है। OpenAI और US अथॉरिटीज़ की तरफ से अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन जारी नहीं किया गया था।
- भारत और किर्गिस्तान ने बिश्केक में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइज़ेशनल स्टडीज़ – मानस और महाभारत का उद्घाटन किया। इसका मकसद कम्पेरेटिव रिसर्च, कल्चरल डिप्लोमेसी और एकेडमिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यह सेंटर महाभारत और मानस महाकाव्य की स्टडी करेगा, जिससे लिटरेचर, फिलॉसफी, इतिहास और इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरडिसिप्लिनरी काम को बढ़ावा मिलेगा। सात किर्गिज़ यूनिवर्सिटी के साथ हुए एग्रीमेंट से फैकल्टी एक्सचेंज, जॉइंट रिसर्च और एजुकेशनल प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगा। इस इवेंट में मानस महाकाव्य का पहला हिंदी ट्रांसलेशन भी रिलीज़ हुआ, जिससे एजुकेशन और स्कॉलरशिप के ज़रिए दोनों देशों के बीच सदियों पुराने कल्चरल और सिविलाइज़ेशनल रिश्ते मज़बूत होंगे।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में तीसरे सालाना समिट के दौरान PACTS (साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन के लिए पार्टनरशिप) लॉन्च किया। यह पहल सरकारों, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी और इनोवेटर्स के बीच सहयोग के ज़रिए साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ज़रूरी मिनरल, डिजिटल रेजिलिएंस और डिफेंस रिसर्च में सहयोग को बढ़ावा देती है। पाँच स्ट्रेटेजिक पिलर्स के आस-पास बने PACTS का मकसद सुरक्षित सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज़ेशन और इनोवेशन को मज़बूत करना है। इसके साथ ही, दोनों देशों ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रिसर्च में तीन-तरफ़ा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप (ACITI) लॉन्च की।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एंथनी अल्बानीज़ ने मेलबर्न में तीसरे इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट के दौरान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप (CSP) को फिर से पक्का किया। दोनों नेताओं ने 2020 से अब तक हुई प्रोग्रेस का रिव्यू किया और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट (CECA) को पूरा करने का वादा किया। बातचीत में डिफेंस, ज़रूरी मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और रिसर्च शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया ने पुरानी भारतीय कलाकृतियों को वापस करने, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के साथ-साथ कल्चरल रिश्तों को मज़बूत करने और एक स्थिर, नियमों पर आधारित इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप को मज़बूत करने की भी घोषणा की।

- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिससे IP ऑस्ट्रेलिया को CSIR और आयुष मंत्रालय द्वारा बनाई गई ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) का एक्सेस मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई पेटेंट एग्ज़ामिनर पारंपरिक ज्ञान पर गलत पेटेंट को रोकने के लिए TKDL को प्रायर आर्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। 2001 में बने इस डेटाबेस में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिग्पा और योग के 5.2 लाख से ज़्यादा फ़ॉर्मूलेशन हैं। ऑस्ट्रेलिया TKDL का एक्सेस रखने वाला 18वां पेटेंट ऑफ़िस बन गया है।
- भारत और न्यूज़ीलैंड ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया और 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करके ₹35,000 करोड़ (NZ$7 बिलियन) करने का लक्ष्य रखा। दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोडमैप 2030 अपनाया, जिसमें व्यापार, खेती, क्लीन एनर्जी, शिक्षा, इनोवेशन, स्किल्स और खेल पर ध्यान दिया गया। हाल ही में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) से आर्थिक सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है। न्यूज़ीलैंड ने लंबे समय के आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए भारत में $20 बिलियन के निवेश की भी घोषणा की।
- UN Women की एक रिपोर्ट में गंभीर मानवीय फंडिंग संकट पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि डोनर सपोर्ट कम होने की वजह से दस लाख से ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों को ज़रूरी मदद नहीं मिल पाई। महिलाओं के नेतृत्व वाले 855 संगठनों के सर्वे में पाया गया कि 40% के एक साल के अंदर बंद होने का खतरा है, जबकि कई ने अपने स्टाफ और सर्विस कम कर दिए हैं। फंडिंग की कमी ने जेंडर-बेस्ड वायलेंस प्रोटेक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थकेयर, एजुकेशन और शेल्टर पर असर डाला है, जिससे महिलाओं के नेतृत्व वाले मानवीय संगठनों में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की मांग उठ रही है।
- 322 लेबर MPs का सपोर्ट मिलने के बाद एंडी बर्नहैम यूनाइटेड किंगडम के अगले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। लेबर पार्टी के नियमों के मुताबिक, एक विरोधी कैंडिडेट के लिए 81 नॉमिनेशन की ज़रूरत होती है, जिससे बर्नहैम का लीडरशिप लगभग पक्का हो गया है। उम्मीद है कि वह कीर स्टारमर की जगह लेंगे, जिन्होंने लेबर के खराब लोकल इलेक्शन परफॉर्मेंस के बाद इस्तीफा दे दिया था। लीडरशिप ट्रांज़िशन से पार्टी की स्ट्रेटेजी को नया शेप मिलने और आने वाले नेशनल इलेक्शन से पहले जनता का भरोसा वापस आने की उम्मीद है।
- भारत और न्यूज़ीलैंड ने 2030 तक के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोडमैप अपनाया, जिसमें डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, टूरिज्म, कल्चर और साइंटिफिक रिसर्च को कवर करने वाले 10 एग्रीमेंट साइन किए गए। मुख्य नतीजों में डिफेंस लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन, काउंटर-टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप, एनिमल हसबैंड्री एग्रीमेंट, नागालैंड और उत्तराखंड में कीवीफ्रूट सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस और बढ़ा हुआ इंडो-पैसिफिक कोऑपरेशन शामिल हैं। दोनों देशों ने ट्रेड, रिन्यूएबल एनर्जी, अंटार्कटिक रिसर्च और एकेडमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने का भी वादा किया।

बैंकिंग/अर्थव्यवस्था/व्यापार समाचार

- मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) 2024-25 को बेस ईयर मानकर इंडेक्स ऑफ़ सर्विसेज़ प्रोडक्शन (ISP) लॉन्च करेगा। यह फॉर्मल सर्विसेज़ सेक्टर को मापने के लिए भारत का पहला मंथली इंडिकेटर होगा, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) में लगभग 53% का योगदान देता है। लैसपेयर वॉल्यूम इंडेक्स मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करके, यह इंडेक्स इंडेक्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) को कॉम्प्लिमेंट करेगा और समय पर पॉलिसी डिसीजन लेने में मदद करेगा। GST डेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड और सेक्टोरल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके इकट्ठा किया गया ISP, भारत के इकोनॉमिक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को काफी मजबूत करेगा।
- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने महेश मुरलीधर पई को 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले तीन साल के टर्म के लिए साउथ इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के तौर पर अपॉइंट करने की मंज़ूरी दे दी है। अभी केनरा बैंक में चीफ़ जनरल मैनेजर के तौर पर काम कर रहे पई के पास डिजिटल बैंकिंग, ट्रेजरी, फ़ॉरेन एक्सचेंज, रिटेल बैंकिंग, MSME फ़ाइनेंस और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में लगभग 30 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। वह PR शेषाद्रि की जगह लेंगे, जिससे त्रिशूर-बेस्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में लीडरशिप मज़बूत होगी।
- इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने भारत के FY2026–27 GDP ग्रोथ के अनुमान को बदलकर 6.4% कर दिया है, जो उसके पहले के अनुमान से थोड़ा कम है, जबकि FY2027–28 के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। यह बदलाव ग्लोबल एनर्जी की ऊंची कीमतों, जियोपॉलिटिकल तनाव और बढ़ी हुई इंपोर्ट लागत को दिखाता है। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसे मजबूत घरेलू मांग और एक मजबूत सर्विस सेक्टर का सपोर्ट मिला है। IMF ने कमोडिटी और एनर्जी की ऊंची कीमतों का हवाला देते हुए अपने ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान को भी घटाकर 3.0% कर दिया।
- फेडरल बैंक को S&P ग्लोबल रेटिंग्स से अपनी पहली इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग मिली, जिससे उसे BBB-/स्टेबल लॉन्ग-टर्म और A-3 शॉर्ट-टर्म रेटिंग मिली। यह पहचान मज़बूत कैपिटलाइज़ेशन, डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफाइड फंडिंग, हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टेबल बिज़नेस ऑपरेशन्स को दिखाती है। इन्वेस्टमेंट-ग्रेड रेटिंग इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाती है, फंडिंग कॉस्ट कम करती है, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है और ग्लोबल कैपिटल मार्केट तक बेहतर एक्सेस देती है। यह माइलस्टोन इंटरनेशनल लेवल पर पहचाने जाने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के बीच फेडरल बैंक की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को मज़बूत करता है, साथ ही भविष्य में बिज़नेस बढ़ाने और सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रोथ में भी मदद करता है।

- वर्ल्ड बैंक ने PM सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना के लिए $890 मिलियन मंज़ूर किए, जिसमें $820 मिलियन का IBRD लोन, $60 मिलियन का क्लीन टेक्नोलॉजी फंड लोन और $10 मिलियन का ग्रांट शामिल है। इस प्रोग्राम का टारगेट एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करना, $4.2 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जुटाना और 1.7 मिलियन नौकरियाँ बनाना है। यह बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए DISCOMs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और वेंडर को भी मज़बूत करता है। यह पहल भारत के नेट-ज़ीरो 2070 टारगेट, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने, एनर्जी सिक्योरिटी और घरों में सोलर पावर अपनाने से सस्ती बिजली पाने में मदद करती है।
- सरकार ने GIFT City IFSC मैरीटाइम यूनिट्स को कोस्टल शिपिंग एक्ट, 2025 के सेक्शन 11 के तहत EXIM ट्रेड में इस्तेमाल होने वाले विदेशी जहाजों को चार्टर करने के लिए लाइसेंस लेने से छूट दे दी है। इस सुधार का मकसद मैरीटाइम लीजिंग, शिप फाइनेंसिंग और मैरीटाइम सर्विसेज़ को बढ़ावा देना है, साथ ही बिज़नेस करने में आसानी को बेहतर बनाना है। मौजूदा कैबोटेज नियम वैसे ही रहेंगे। इस कदम से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आने और GIFT City के एक इंटरनेशनल मैरीटाइम और फाइनेंशियल सर्विसेज़ हब के तौर पर मज़बूत होने की उम्मीद है।
- भारत ने चीन से इंपोर्ट होने वाले सीमलेस स्टील ट्यूब और पाइप पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी 27 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी है। यह फैसला डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ ट्रेड रेमेडीज़ (DGTR) के सनसेट रिव्यू के बाद लिया गया, जिसमें यह नतीजा निकला कि ड्यूटी हटाने से घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो सकता है। कस्टम्स टैरिफ हेडिंग 7304 के तहत आने वाले प्रोडक्ट्स पर लागू, यह कदम भारतीय स्टील इंडस्ट्री को गलत कीमत वाले इंपोर्ट से बचाता है और फेयर कॉम्पिटिशन को सपोर्ट करता है।
- इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) और जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड ने गुजरात में गन्ने की खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए एक MoU साइन किया है। इस पार्टनरशिप में फील्ड सर्वे, सिस्टम डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, किसान ट्रेनिंग और फर्टिगेशन सपोर्ट शामिल हैं। किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अपनाने के लिए मदद मिलेगी, जिसमें क्रेडिट और सरकारी ग्रांट तक पहुंच शामिल है। इस पहल का मकसद पानी के इस्तेमाल की एफिशिएंसी में सुधार करना, फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देना और भारत के बायोफ्यूल फीडस्टॉक इकोसिस्टम को मजबूत करना है।

नियुक्तियाँ/इस्तीफ़े

- केंद्र सरकार ने कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी से मंज़ूरी के बाद तीन बड़े पुलिस इंस्टीट्यूशन के नए हेड अपॉइंट किए। आलोक कुमार मित्तल BPR&D के डायरेक्टर जनरल बने, अमित गर्ग NCRB के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए, और सुजीत पांडे SVPNPA, हैदराबाद के डायरेक्टर बने। इन अपॉइंटमेंट का मकसद पुलिस मॉडर्नाइज़ेशन को मज़बूत करना, क्राइम डेटा मैनेजमेंट को बेहतर बनाना और IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग को बेहतर बनाना है। BPR&D, मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है, जबकि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड मैनेज करता है और SVPNPA इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर को ट्रेनिंग देता है।
- विदेश मंत्रालय (MEA) ने 2008 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) ऑफिसर संजीव जैन को नॉर्थ कोरिया (DPRK) में भारत का एम्बेसडर अपॉइंट किया है। पहले काबो वर्डे में एम्बेसडर के तौर पर काम कर चुके जैन के पास भारत के बाइलेटरल रिश्तों को मजबूत करने का बहुत डिप्लोमैटिक अनुभव है। वे ज़रूरी डिप्लोमैटिक फॉर्मैलिटी पूरी करने के बाद चार्ज संभालेंगे। उनके अपॉइंटमेंट से भारत-नॉर्थ कोरिया डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट बढ़ने, भारत के बड़े फॉरेन पॉलिसी के मकसद को सपोर्ट करने, और लगातार डिप्लोमैटिक बातचीत और स्ट्रेटेजिक तरीकों से रीजनल और इंटरनेशनल मामलों पर कोऑपरेशन मजबूत होने की उम्मीद है।

रक्षा समाचार

- अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पाली में ₹2,500 करोड़ की मिसाइल बनाने की फैसिलिटी के लिए फाउंडेशन का काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में मीडियम और लॉन्ग-रेंज मिसाइल सिस्टम के साथ-साथ कम्पोजिट प्रोपेलेंट, TNT और दूसरे एक्सप्लोसिव मटीरियल बनाए जाएंगे। इसे तीन साल में पूरा करने का प्लान है और इससे लगभग 5,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, साथ ही 50 से ज़्यादा MSMEs को भी जोड़ा जाएगा। यह फैसिलिटी भारत के डिफेंस बनाने के इकोसिस्टम को मजबूत करेगी, आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेगी और देश की स्वदेशी मिसाइल बनाने की क्षमताओं को बढ़ाएगी।
- प्रोजेक्ट 17A (नीलगिरी -क्लास) के तहत छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट, INS महेंद्रगिरी (F38), 11 जुलाई 2026 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा 75% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री के साथ बनाया गया, इस युद्धपोत में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पनडुब्बी रोधी क्षमताएं और एक CODOG प्रोपल्शन सिस्टम हैं। यह पूर्वी बेड़े में शामिल होगा, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा मज़बूत होगी और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर भारत पहल को समर्थन मिलेगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच बातचीत के दौरान इंडोनेशिया ने भारत की स्वदेशी एस्ट्रा बियॉन्ड-विजुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) को इंपोर्ट करने का फैसला किया। DRDO द्वारा डेवलप और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा बनाई गई, एस्ट्रा भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइल है। इस एग्रीमेंट में ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई, इंडोनेशिया-स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और सबांग पोर्ट के डेवलपमेंट के ज़रिए बढ़ा हुआ सहयोग भी शामिल है। यह डील भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को मज़बूत करती है, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करती है, और इंडो-पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक सहयोग को बढ़ाती है।
- डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR) का सफल फ्लाइट-टेस्ट किया। रॉकेट ने 60 km की अपनी मिनिमम ऑपरेशनल रेंज को सही-सही दिखाया, सभी प्लान किए गए मैनूवर को सफलतापूर्वक पूरा किया और टारगेट को बहुत सटीकता से हिट किया। ARDE, HEMRL, DRDL और RCI द्वारा डेवलप किया गया LRGR, पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) सिस्टम को एडवांस्ड गाइडेंस, नेविगेशन और सटीक स्ट्राइक क्षमताओं के साथ बेहतर बनाता है, जिससे भारत का आत्मनिर्भर भारत मजबूत होता है। रक्षा कार्यक्रम.

- CSIR -NAL ने स्वदेशी सरस MkII का डिज़ाइन चरण पूरा कर लिया है। 19-सीटर ट्विन-टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट , जो भारत के एविएशन प्रोग्राम में एक बड़ा मील का पत्थर है। UDAN स्कीम के तहत रीजनल कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया , इसमें प्रेशराइज़्ड केबिन , ग्लास कॉकपिट , डिजिटल एवियोनिक्स , ऑटोपायलट और कमांड-बाय-वायर फ़्लाइट कंट्रोल हैं । HAL प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट प्रोडक्शन में मदद करेगा, जबकि पहली फ़्लाइट दिसंबर 2027 के लिए तय है। इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) ने 15 एयरक्राफ्ट की शुरुआती ज़रूरत बताई है , जिससे पूरे भारत में स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता, सिविल एविएशन और डिफ़ेंस ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन मज़बूत होंगे।

पुरस्कार और सम्मान

- इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (ICMR) को अपने AI-पावर्ड मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, ICMR-MINDS के लिए ई-गवर्नेंस 2026 के लिए नेशनल अवार्ड्स में गोल्ड अवार्ड मिला । इस अवार्ड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए नागरिक-केंद्रित हेल्थकेयर सर्विस देने में इनोवेशन को मान्यता दी । यह प्लेटफॉर्म मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग , असेसमेंट , ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन और फॉलो-अप केयर में फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर्स की मदद करने के लिए AI-बेस्ड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (CDSS) का इस्तेमाल करता है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट , ऑफलाइन फंक्शनैलिटी और रियल-टाइम डैशबोर्ड की सुविधा के साथ , ICMR-MINDS का मकसद पूरे भारत में एक्सेसिबल और एविडेंस-बेस्ड मेंटल हेल्थकेयर को बेहतर बनाना है।
- अहमदाबाद के आचार्य रणछोड़लाल गोस्वामी को हवेली संगीत को बचाने के लिए संगीत नाटक अकादमी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना है । ऐतिहासिक गोस्वामी हवेली के 16वीं पीढ़ी के आचार्य ने 2,200 से ज़्यादा भक्ति पद्य रचे हैं , आठ किताबें लिखी हैं , गुजरात यूनिवर्सिटी के हवेली संगीत करिकुलम में योगदान दिया है, और संगीत में डॉक्टरेट रिसर्च जारी रखे हुए हैं। यह पुरस्कार 550 साल पुरानी पुष्टिमार्ग भक्ति संगीत परंपरा को बचाने की उनकी कोशिशों को पहचान देता है , जो भारत की क्लासिकल संगीत विरासत का एक ज़रूरी हिस्सा है।
- डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) ने भारतनेट से चलने वाले एक इंटीग्रेटेड फिजिटल रूरल सर्विस डिलीवरी मॉडल , समृद्ध ग्राम के लिए प्रतिष्ठित WSIS प्राइज़ 2026 जीता। एक्शन लाइन C6 के तहत अवार्डेड , यह पहल गांव-लेवल सेंटर्स के ज़रिए हेल्थकेयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इनक्लूजन, गवर्नेंस और डिजिटल सर्विसेज़ देने वाले समृद्धि केंद्र बनाती है। 2.17 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में भारतनेट की कनेक्टिविटी के सपोर्ट से , इस प्रोजेक्ट को ITU के इवैल्यूएशन और 2.2 मिलियन से ज़्यादा ग्लोबल वोटों के बाद चुना गया , जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और इनक्लूसिव रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारत की लीडरशिप को दिखाता है ।

योजना समाचार

- यूपी महिला सामर्थ्य योजना, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (UPSRLM) के तहत सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) के ज़रिए ग्रामीण महिलाओं को मज़बूत बनाती है । यह स्कीम मुफ़्त स्किल ट्रेनिंग , ₹15,000 का रिवॉल्विंग फंड , एंटरप्रेन्योरशिप में मदद और क्लस्टर लेवल एंटरप्राइजेज (CLEs) के ज़रिए मार्केट लिंकेज देती है। एलिजिबल बेनिफिशियरी में 18-60 साल की महिलाएं शामिल हैं , जिनमें BPL परिवारों , SC/ST कम्युनिटी , दिव्यांग महिलाओं और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को प्रायोरिटी दी गई है। यह पहल पूरे ग्रामीण उत्तर प्रदेश में फाइनेंशियल इनक्लूजन , महिलाओं के नेतृत्व वाले एंटरप्राइजेज, सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल रोजी-रोटी और सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है।
- उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए UP निःशुल्क बोरिंग योजना 2026 लागू करेगी। इसके लिए मुफ़्त खेती के बोरवेल लगवाने और सब्सिडी पर सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। योग्य किसानों के लिए 5 HP तक के पंप सेट । मूल रूप से 1985 में शुरू की गई यह स्कीम छोटे , सीमांत और SC/ST किसानों को टारगेट करती है, जिससे मॉनसून की बारिश पर निर्भरता कम होती है और ग्राउंडवॉटर तक पहुंच बेहतर होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उत्तर प्रदेश माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए एप्लीकेशन जमा किए जा सकते हैं । इस पहल से पूरे राज्य में सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, फसल की पैदावार बढ़ाने, गांव के लोगों की रोजी-रोटी में सुधार करने और खेती की लागत कम करने की उम्मीद है।
- UP महिला उद्यम निधि योजना 2026 महिला एंटरप्रेन्योर्स को माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज शुरू करने या बढ़ाने के लिए लगभग 4% इंटरेस्ट पर ₹50,000 से ₹10 लाख तक की फाइनेंशियल मदद देती है । ₹2 लाख तक के लोन बिना किसी कोलैटरल के मिलते हैं। सेल्फ-हेल्प ग्रुप (SHG) मेंबर्स , विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और माइनॉरिटी महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाती है । यह स्कीम पूरे उत्तर प्रदेश में महिला एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल इनक्लूजन, एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ावा देती है।

खेल समाचार

- ब्राज़ील के फ़ुटबॉल के दिग्गज नेमार जूनियर ने मेटलाइफ़ स्टेडियम में नॉर्वे से ब्राज़ील की 2-1 से FIFA विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ़ 16 की हार के बाद इंटरनेशनल फ़ुटबॉल से संन्यास ले लिया । 16 साल के इंटरनेशनल करियर का अंत करते हुए , नेमार ने ब्राज़ील के लिए आखिरी समय में पेनल्टी पर एकमात्र गोल किया । वे 130 मैचों में 80 गोल और 59 असिस्ट के साथ ब्राज़ील के ऑल-टाइम लीडिंग पुरुष स्कोरर के तौर पर रिटायर हो रहे हैं । उनकी उपलब्धियों में 2013 FIFA कन्फ़ेडरेशन कप और 2016 ओलंपिक गोल्ड मेडल शामिल हैं , हालाँकि उनके शानदार इंटरनेशनल करियर के दौरान FIFA विश्व कप का टाइटल उनसे दूर ही रहा।
- ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को सात विकेट से हराकर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल जीता , और रिकॉर्ड सातवीं चैंपियनशिप पक्की की । इंग्लैंड ने कैप्टन नैट साइवर-ब्रंट के नाबाद 58 रन की मदद से 150/4 का स्कोर बनाया , लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवर में 153/3 का स्कोर आराम से हासिल कर लिया । बेथ मूनी ने 64 रन बनाकर पारी को संभाला और प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवॉर्ड जीता, जबकि फोएबे लिचफील्ड ने 48 रन बनाए । इस जीत ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे सफल टीम के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की पहचान को और मज़बूत किया ।

- वैभव सूर्यवंशी 15 साल और 99 दिन की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए , उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ T20I में डेब्यू किया । उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 16 साल और 205 दिन की उम्र में डेब्यू करने के लंबे समय के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया । वैभव भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष T20I डेब्यू करने वाले खिलाड़ी भी बने , जिससे देश में उभरते क्रिकेट टैलेंट पाइपलाइन का पता चला। हालांकि, सबसे कम उम्र के पुरुष T20I इंटरनेशनल का ओवरऑल रिकॉर्ड रोमानिया के मैरियन घेरासिम के नाम है , जबकि आयरलैंड के जोशुआ लिटिल ने पहले फुल ICC मेंबर्स में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था ।
- चार्ल्स लेक्लर्क ने सिल्वरस्टोन में 2026 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता , और एक एक्शन से भरपूर रेस के बाद फेरारी के लिए अपनी नौवीं फ़ॉर्मूला वन जीत हासिल की। मैक्स वर्स्टैपेन के क्रैश की वजह से देर से आई एक सेफ़्टी कार ने फ़ाइनल स्टैंडिंग को लॉक कर दिया। जॉर्ज रसेल मर्सिडीज़ के लिए दूसरे स्थान पर रहे , जबकि रेस के बाद की जांच के बावजूद लुईस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। लैंडो नॉरिस मैकलारेन के लिए चौथे स्थान पर रहे , और किमी एंटोनेली मैकेनिकल दिक्कतों और पेनल्टी के बाद सोलहवें स्थान पर आ गए। फेरारी की मज़बूत स्ट्रैटेजी और लगातार रफ़्तार ने सीज़न की सबसे रोमांचक रेस में से एक में यादगार जीत दिलाई।
- भारत ग्लासगो में 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान एक इंटरनेशनल मल्टी-स्पोर्ट इवेंट में अपने एथलीटों को जूट-विस्कोस ब्लेंडेड कपड़े पहनाने वाला पहला देश बन जाएगा। नेशनल जूट बोर्ड (NJB) , ग्लॉस्टर जूट मिल्स और NIFT द्वारा डेवलप की गई ये यूनिफॉर्म 100% बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक से बनी हैं, जो सस्टेनेबल टेक्सटाइल और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती हैं । भारत का 124 सदस्यों वाला दल ऑफिशियल सेरेमनी के दौरान इको-फ्रेंडली कपड़े पहनेगा, जो इनोवेशन, एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वैल्यू-एडेड जूट प्रोडक्ट्स और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के कमिटमेंट को हाईलाइट करेगा।
- FIFA वर्ल्ड कप 2026 राउंड ऑफ़ 16 पूरा होने के बाद क्वार्टरफ़ाइनल स्टेज में पहुँच गया। फ़्रांस , मोरक्को , स्पेन , बेल्जियम , नॉर्वे , इंग्लैंड , अर्जेंटीना और स्विट्ज़रलैंड आखिरी आठ में पहुँच गए। क्वार्टरफ़ाइनल में फ़्रांस बनाम मोरक्को , स्पेन बनाम बेल्जियम , नॉर्वे बनाम इंग्लैंड और अर्जेंटीना बनाम स्विट्ज़रलैंड के मैच शामिल हैं , जो 10-12 जुलाई 2026 (IST) तक होने हैं । जीतने वाली टीमें फ़ाइनल से पहले दो सेमीफ़ाइनल खेलेंगी। बाकी मैचों में कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि टीमें फ़ुटबॉल के सबसे बड़े इंटरनेशनल टाइटल के लिए लड़ेंगी।
- कन्याकुमारी के सत्रह साल के अश्वथ एस 2026 पुणे इंटरनेशनल ग्रैंडमास्टर राउंड रॉबिन में अपना आखिरी ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 98वें चेस ग्रैंडमास्टर बन गए । उन्होंने आखिरी राउंड में FM कन्नन वैद्यनाथन को हराकर यह टाइटल जीता , जिसमें उन्होंने 9 गेम में 7 पॉइंट हासिल किए। इससे पहले, उन्होंने ग्रेंके ओपन और बुडापेस्ट फर्स्ट सैटरडे GM टूर्नामेंट में ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किए थे , साथ ही ज़रूरी 2500 FIDE रेटिंग भी पार की थी , जिससे दुनिया भर में चेस की बड़ी ताकत के तौर पर भारत की बढ़ती साख और मज़बूत हुई।
- तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) 2026 को होस्ट करेगा , जो युवा एथलीटों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म देगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय के खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत आयोजित इन गेम्स का मकसद भविष्य के चैंपियन की पहचान करना, जमीनी स्तर के खेलों को मजबूत करना और एथलीटों को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करना है। इस इवेंट में हजारों लोग, कोच और अधिकारी आएंगे, जिससे स्पोर्ट्स टूरिज्म , आर्थिक गतिविधि और युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तेलंगाना का चुनाव इसके बढ़ते स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाता है और एक मजबूत स्पोर्ट्स कल्चर बनाने के भारत के लंबे समय के विजन को सपोर्ट करता है।
- पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को मशहूर ICC हॉल ऑफ़ फ़ेम में शामिल किया गया , और वे यह सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए । अपनी निडर लीडरशिप के लिए पहचाने जाने वाले गांगुली ने टीम को 2003 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप फ़ाइनल तक पहुँचाकर और MS धोनी , युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग जैसे भविष्य के सितारों को तैयार करके भारतीय क्रिकेट को बदल दिया। अपने करियर के दौरान, उन्होंने 113 टेस्ट और 308 ODI खेले । यह सम्मान उनकी शानदार उपलब्धियों, लीडरशिप और भारत को क्रिकेट की सबसे मज़बूत इंटरनेशनल टीमों में से एक बनाने में उनके लंबे समय तक चलने वाले योगदान को सेलिब्रेट करता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार

- जापान के हायाबुसा2 स्पेसक्राफ्ट , जिसे JAXA चलाता है , ने 5 जुलाई 2026 को एस्टेरॉयड टोरिफ्यून (2001 CC21) के पास से तेज़ी से गुज़रते हुए कामयाबी से उड़ान भरी । 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ़्तार से चलते हुए , यह एस्टेरॉयड के सेंटर से लगभग 800 मीटर दूर से गुज़रा ताकि उसकी सतह , बनावट और तापमान की स्टडी की जा सके । यह मिशन एडवांस्ड नेविगेशन , सटीक गाइडेंस और तेज़ी से टोही टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग करके ग्रहों की सुरक्षा रिसर्च को सपोर्ट करता है। 2020 में अपने कामयाब रयुगु सैंपल-रिटर्न मिशन के बाद , हायाबुसा2 एस्टेरॉयड 1998 KY26 की ओर अपना बड़ा मिशन जारी रखेगा , जिसका टारगेट 2031 है ।
- इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) ने गगनयान मिशन के तहत सतीश धवन स्पेस सेंटर , श्रीहरिकोटा में सब-ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स (SOLVE) का पहला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है । इस टेस्ट ने व्हीकल के सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम को वैलिडेट किया, जिसे 10-17 km की ऊंचाई से क्रू मॉड्यूल रिकवरी , पैराशूट डिप्लॉयमेंट और सेफ वॉटर लैंडिंग को एवैल्यूएट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है । मॉडिफाइड PSLV-बेस्ड प्रोपल्शन और एडवांस्ड नोजल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, SOLVE भारत के पहले स्वदेशी ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन की तैयारियों को मजबूत करता है , जिससे क्रू सेफ्टी और स्पेस मिशन रिलायबिलिटी बढ़ती है।
- चीन ने साउथ पैसिफिक में सबमरीन-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) का टेस्ट किया , जो 1982 के बाद किसी न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन से उसका पहला सबमरीन-बेस्ड स्ट्रेटेजिक मिसाइल लॉन्च था । मिसाइल में एक डमी वॉरहेड था और इसे रूस के साथ जॉइंट सी-2026 नेवल एक्सरसाइज के दौरान लॉन्च किया गया था। इस टेस्ट ने ऑस्ट्रेलिया , न्यूज़ीलैंड और जापान की चिंता बढ़ाई , साथ ही चीन की समुद्र पर आधारित न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमताओं को भी हाईलाइट किया । इस लॉन्च ने रारोटोंगा (1985) की संधि पर भी फिर से ध्यान खींचा , जिसने साउथ पैसिफिक को न्यूक्लियर-फ्री ज़ोन बनाया ।

- चीनी AI स्टार्टअप डीपसीक विदेशी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करने के लिए एक कस्टम AI इंफरेंस चिप बना रहा है। चीन की लीडिंग सेमीकंडक्टर फाउंड्री SMIC के साथ मिलकर बनाई गई यह चिप मुख्य रूप से AI इंफरेंस के लिए डिज़ाइन की गई है , जिससे अच्छे से टेक्स्ट, इमेज और प्रेडिक्शन जेनरेशन हो सके। डीपसीक के V4-Pro और V4-Flash मॉडल Huawei Ascend प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं , जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पाबंदियों के बीच चीन के घरेलू AI इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। यह पहल चीन की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता को मज़बूत करती है, स्वदेशी AI हार्डवेयर को आगे बढ़ाती है, और लंबे समय तक टेक्नोलॉजिकल आज़ादी को सपोर्ट करती है।
- US फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने ER-पॉज़िटिव , HER2-नेगेटिव , ESR1-म्यूटेटेड एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर के लिए दुनिया की पहली PROTAC-बेस्ड दवा के तौर पर वेपडेगेस्ट्रेंट (वेप्पनु) को मंज़ूरी दी है। अर्विनास और फ़ाइज़र की बनाई इस दवा ने फ़ेज़ 3 VERITAC-2 ट्रायल में बेहतर परफ़ॉर्मेंस दिखाई , और फ़ुलवेस्ट्रेंट के मुकाबले प्रोग्रेस-फ़्री सर्वाइवल में सुधार किया। FDA ने ESR1 म्यूटेशन का पता लगाने के लिए एक साथी डायग्नोस्टिक के तौर पर गार्डेंट360 CDx को भी मंज़ूरी दी है। यह मंज़ूरी इनोवेटिव प्रोटीन डिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए टारगेटेड कैंसर थेरेपी में एक बड़ी कामयाबी है।
- इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट-05 (IMAT-05) सफलतापूर्वक किया । इंडियन एयर फ़ोर्स के IL-76 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके 2.5 km की ऊंचाई से एक सिम्युलेटेड क्रू मॉड्यूल गिराया गया , जिससे पैराशूट डिप्लॉयमेंट का पूरा सीक्वेंस और सुरक्षित डिसेंट वैलिडेट हुआ। ISRO , DRDO , इंडियन एयर फ़ोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर यह सफल टेस्ट किया, जिससे गगनयान G1 मिशन और भारत के पहले स्वदेशी ह्यूमन स्पेसफ़्लाइट प्रोग्राम की तैयारियों को मज़बूती मिली है।
- मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ (MoRTH) ने IIT मद्रास और C-DAC को नेशनल ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम सौंपा है , जो ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम (BHMS) को सपोर्ट करता है । एडवांस्ड सेंसर का इस्तेमाल करके, यह सिस्टम बेहतर स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए ब्रिज के स्ट्रेस, वाइब्रेशन, मूवमेंट और लोड को मॉनिटर करता है। NHAI , NHIDCL , BRO और राज्य PWDs जैसी एजेंसियों को 30 सितंबर 2026 तक पूरे देश में डिजिटल ब्रिज इन्वेंट्री पूरी करनी होगी। यह पहल पूरे भारत में सेंट्रलाइज़्ड डेटा एनालिसिस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बेहतर ब्रिज सेफ्टी और कुशल लॉन्ग-टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को मुमकिन बनाती है।
- नोवो नॉर्डिस्क इंडिया ने Awiqli (इंसुलिन icodec) लॉन्च किया है , जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वाले बड़ों के लिए दुनिया का पहला हफ़्ते में एक बार दिया जाने वाला बेसल इंसुलिन है। इस थेरेपी से हर साल लगने वाले इंजेक्शन की संख्या 365 से घटकर 52 हो जाती है , जिससे मरीज़ को आसानी होती है और इलाज का पालन बेहतर होता है। FlexTouch डिवाइस से दिया जाने वाला Awiqli पूरे हफ़्ते स्टेबल ग्लूकोज़ कंट्रोल देता है। ONWARDS-1 ट्रायल के क्लिनिकल नतीजों में रोज़ाना इंसुलिन की तुलना में HbA1c में बेहतर कमी , बेहतर Time in Range , और हाइपोग्लाइसीमिया की कम चिंताएँ दिखीं । यह इनोवेशन भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ 101 मिलियन से ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं।
- साइंटिस्ट्स ने स्पर्म व्हेल्स के बीच स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन को डिकोड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया , जिससे फोनेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे 156 अलग-अलग कोडा की पहचान हुई। प्रोजेक्ट CETI (सिटेशियन ट्रांसलेशन इनिशिएटिव) के तहत किए गए इस रिसर्च में 2005 और 2018 के बीच इकट्ठा की गई लगभग 400 व्हेल्स की रिकॉर्डिंग को एनालाइज़ किया गया । नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश हुई इस स्टडी में रूबाटो और ऑर्नामेंटेशन समेत कम्युनिकेशन फीचर्स की पहचान की गई , जो सोफिस्टिकेटेड वोकल पैटर्न का सुझाव देते हैं। रिसर्चर्स ने बिहेवियरल डेटा इकट्ठा करने के लिए AI-पावर्ड बायो-लॉगर्स और ऑटोनॉमस अंडरवाटर ग्लाइडर्स भी डेवलप किए , जो मरीन बायोलॉजी और एनिमल कम्युनिकेशन रिसर्च में AI की बढ़ती भूमिका को दिखाते हैं।

महत्वपूर्ण दिन

- जानवरों और इंसानों के बीच फैलने वाली ज़ूनोटिक बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 जुलाई को वर्ल्ड ज़ूनोसेस डे 2026 मनाया गया। यह दिन 6 जुलाई 1885 को लुई पाश्चर द्वारा पहली रेबीज़ वैक्सीन के सफल इस्तेमाल की याद में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) के अनुसार , इंसानों में होने वाली लगभग 60% संक्रामक बीमारियाँ जानवरों से होती हैं। यह दिन वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देता है, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स , जानवरों के डॉक्टरों और पर्यावरण विशेषज्ञों के बीच सहयोग पर ज़ोर दिया जाता है। बचाव के मुख्य उपायों में वैक्सीनेशन , निगरानी , साफ़-सफ़ाई , सुरक्षित खाने की हैंडलिंग और लोगों में जागरूकता शामिल है।
- 6 जुलाई 2026 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई , जिसमें एक पॉलिटिकल लीडर , एजुकेशनिस्ट और नेशनलिस्ट के तौर पर उनके योगदान को सम्मान दिया गया। 1901 में जन्मे , वे 1934 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के वाइस-चांसलर बने , और उन्होंने बड़े एजुकेशनल सुधार किए। आज़ादी के बाद, उन्होंने भारत की पहली यूनियन कैबिनेट में इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर के तौर पर काम किया और 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की , जो बाद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) बनी। उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन और "एक देश, एक संविधान" के सिद्धांत की ज़ोरदार वकालत की।
- वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को पॉपुलेशन से जुड़े मुद्दों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वालिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2026 की थीम है "युवा लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना: आज और भविष्य में।" UNDP ने 1989 में इसे शुरू किया था, यह दिन शिक्षा, हेल्थकेयर, रिप्रोडक्टिव अधिकारों और युवाओं के एम्पावरमेंट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है । सरकारें और संगठन इनक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के एम्पावरमेंट और सस्टेनेबल पॉपुलेशन मैनेजमेंट को बढ़ावा देने वाले जागरूकता प्रोग्राम चलाते हैं।

निधन समाचार

- पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित गिरीश भारद्वाज , जिन्हें "ब्रिज मैन ऑफ़ इंडिया" के नाम से जाना जाता है, का 76 साल की उम्र में निधन हो गया । एक मैकेनिकल इंजीनियर और ज़मीनी स्तर के इनोवेटर, उन्होंने कर्नाटक , केरल , तेलंगाना और ओडिशा में 140 से ज़्यादा कम लागत वाले सस्पेंशन ब्रिज बनाए , जो दूर के गांवों को स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट से जोड़ते थे। उनका पहला पुल, जो 1989 में पयस्विनी नदी पर बना था , मुश्किल इलाकों के लिए सस्ती इंजीनियरिंग की शुरुआत थी। भारद्वाज के काम ने गांवों की कनेक्टिविटी को बदल दिया और वे इनक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर , इनोवेशन और सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट की एक हमेशा रहने वाली पहचान बने हुए हैं।

स्टेटिक टेकअवे

पहलू	विवरण
गुजरात	राज्यपाल: आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री : भूपेंद्र पटेल, राजधानी: गांधीनगर
महाराष्ट्र	राज्यपाल: जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री : देवेंद्र फडणवीस, राजधानी: मुंबई
बिहार	राज्यपाल: आरिफ खान, मुख्यमंत्री : सम्राट चौधरी, राजधानी: पटना
राजस्थान	राज्यपाल: हरिभाऊ बागड़े , मुख्यमंत्री : भजनलाल शर्मा, राजधानी: जयपुर
हरयाणा	राज्यपाल: अशीम कुमार घोष , मुख्यमंत्री : नायब सैनी, राजधानी: हरियाणा
दिल्ली	राज्यपाल: तरनजीत सिंह, मुख्यमंत्री : रेखा गुप्ता, राजधानी: नई दिल्ली
पश्चिम बेंग्रल	राज्यपाल: आरएन रवि, मुख्यमंत्री : सुवेंदु अधिकारी, राजधानी: कोलकाता
ओडिशा	राज्यपाल: हरिबाबू खंभापति, मुख्यमंत्री : मोहन माझी, राजधानी: भुवनेश्वर
सऊदी अरब	देश के प्रमुख: मोहम्मद बिन सलमान
यूएसए	राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी: वाशिंगटन डी.सी.
इज़राइल	प्रधानमंत्री: बेंजामिन नेतनहायु राजधानी: यरुशलम
ऑस्ट्रेलिया	प्रधानमंत्री: एंथनी अल्बानसे
न्यूज़ीलैंड	प्रधानमंत्री: लक्सन क्रिस्टोफर
जापान	प्रधानमंत्री: साने ताकाची, राजधानी: टोक्यो
भारतीय रिजर्व बैंक	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा
ओपनएआई	संस्थापक: सैम ऑल्टमैन
आईसीसी अध्यक्ष	जय शाह

Test Prime By Adda247

ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION

Test. Analyze. Improve. Repeat.

Don't just prepare. Perform.

Test Prime – built only for mock tests.

1,50,000+ Mock Tests

25,000+ Previous Year Papers

800+ Exam Covered

500% Refund on Selection

5 lakh+ Free Quizzes

Daily Free PDFs

Top Alerts Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- Multilingual
- Detailed Solution
- Strong and Weak Areas
- All India Rankings

- Safe & Reliable
- Trusted by Lakhs of Aspirants
- Your Success, Our Mission

DOWNLOAD TEST PRIME

Your Success Partner!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store